

उत्तराखण्ड में बनेंगे ड्रोन कॉरडोर

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिये कॉरडोर बनाए जाएंगे। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने ड्रोन संचालन व नरिमाण कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं।

प्रमुख बिंदु

- आईटीडीए की नदिशक नतिका खंडेलवाल ने बताया कि पिछले दिनों ड्रोन नीति बनाने के दौरान सभी हतिधारकों की बैठक हुई थी। इसमें हतिधारकों वशिषकर ड्रोन नरिमाता व संचालकों से संभावति ड्रोन कॉरडोर का प्रस्ताव मांगा गया है।
- उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव आने के बाद राज्य के हवाई नकशे के हसिाब से इसका अधूयन कया जाएगा। फरि उत्तराखण्ड नागरकि उड्डयन वकिसा प्राधकिरण (यूकाडा) के माधूयम से नागर वमिानन महानदिशालय (डीजीसीए) को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद राज्य में ड्रोन के कॉरडोर तय हो जाएंगे। सभी ज़िलों में ड्रोन संचालन के लिये जो कॉरडोर बनेंगे, उन्हें आपस में लकि कया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समरूपति रास्तों का पूरा नेटवरक तैयार हो जाएगा। नयिम को तोडने वालों पर भवषिय में कार्रवाई भी हो सकेगी।
- ड्रोन कॉरडोर बनाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार कयि जाएंगे, जो हवाई सेवाओं को बाधति न करें। वही, सीमांत प्रदेश होने के नाते तमाम प्रतबिंधति क्षेत्रों को भी सुरकषा प्रदान की जाएगी।
- ज़ातवूय है कि वर्तमान में प्रदेश में उत्तरकाशी से दून या अन्य जगहों पर ड्रोन संचालन का कोई समरूपति कॉरडोर नहीं है, जसिसे कई ड्रोन को लंबी दूरी तय करनी पडती है। इससे अधकि समय लगने और ड्रोन की बैटरी भी जल्द खतम होने का खतरा है। ड्रोन कॉरडोर के बन जाने से उडान का समय तो कम होगा ही, उसकी बैटरी भी लंबी दूरी की उडान में मदद करेगी।
- ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे वकिसा के मददेनजर उत्तराखण्ड सरकार जल्द ही ड्रोन नीति लाने जा रही है। आईटीडीए ने इसका ड्राफ्ट शासन को भेजा है। इसके तहत ड्रोन संचालन से लेकर ड्रोन की खरीद तक के सभी प्रावधान कयि जाएंगे।



